

RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

Key Point

DATE

नवम्बर

23

2024

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index



By Ankit Avasthi Sir

कार्बन क्रेडिट तंत्र / Carbon credit mechanism

हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि केवल 16% कार्बन क्रेडिट ही वास्तविक उत्सर्जन में कमी लाते हैं। यह खुलासा कार्बन बाजारों की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसे समय में जब COP29 में नए कार्बन व्यापार तंत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है, यह अध्ययन उत्सर्जन में कमी के दावों की सटीकता पर पुनर्विचार की आवश्यकता दर्शाता है।

अध्ययन की मुख्य खोज और समाधान सुझाव:

- कार्बन क्रेडिट की प्रभावशीलता पर सवाल:**
 - क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के तहत उत्पन्न एक अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) के बराबर कार्बन क्रेडिट में से केवल 16% क्रेडिट वास्तविक उत्सर्जन में कमी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- HFC-23 परियोजनाओं की सफलता:**
 - हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC)-23**, जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, के उन्मूलन पर केंद्रित परियोजनाएँ सबसे प्रभावी रहीं। इनसे उत्पन्न 68% क्रेडिट ने उत्सर्जन में वास्तविक कटौती की।
- अन्य परियोजनाओं की सीमाएँ:**
 - वनों की कटाई से बचाव परियोजनाएँ** केवल 25% प्रभावशीलता दिखा पाईं, जबकि सौर कुकर परिनियोजन परियोजनाएँ महज़ 11% क्रेडिट की वास्तविक उत्सर्जन कटौती में सहायक रहीं।
- "अतिरिक्तता" नियम का उल्लंघन:**
 - अध्ययन में पाया गया कि कई परियोजनाएँ "अतिरिक्तता" (additionality) के मानक पर खरी नहीं उतरीं। इसका अर्थ है कि उत्सर्जन में कमी कार्बन क्रेडिट के बिना भी संभव थी, जिससे दावा कमजोर हो गया।
- पेरिस समझौते के तहत नई दिशा:**
 - पेरिस समझौते, 2015 के तहत अधिक सख्त और मज़बूत कार्बन व्यापार तंत्र की आवश्यकता है। इसे सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट केवल वास्तविक उत्सर्जन कटौती का प्रतिनिधित्व करें।
- सिफारिशें और सुधार के उपाय:**
 - सख्त पात्रता मानदंड:** उत्सर्जन में वास्तविक कमी को मापने के लिये सटीक मानकों और पद्धतियों की आवश्यकता।
 - अतिरिक्तता आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता:** जिन परियोजनाओं में कार्बन क्रेडिट के बिना उत्सर्जन कटौती संभव न हो, उन्हें बढ़ावा देना।
 - COP29 में प्रगति की उम्मीद:** यह सम्मेलन कार्बन बाजारों की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये नए तंत्र लागू करने का अवसर प्रदान करता है।

कार्बन क्रेडिट: कार्बन क्रेडिट एक ऐसा प्रमाणपत्र है जो धारक को एक टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) या उसके समकक्ष ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जित करने का अधिकार देता है। यह तंत्र पर्यावरण संरक्षण और उत्सर्जन में कमी को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है।

कार्बन क्रेडिट कैसे बनते हैं?

कार्बन क्रेडिट उन गतिविधियों या परियोजनाओं से उत्पन्न होते हैं जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या वायुमंडल से हटाने में सहायक होती हैं, जैसे:

- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ:** सौर और पवन ऊर्जा।
- ऊर्जा दक्षता:** ऊर्जा खपत को कम करने वाले उपाय।
- वनरोपण:** वनों का पुनर्विकास।
- मीथेन संग्रहण:** लैंडफिल और औद्योगिक स्थलों से।

कार्बन क्रेडिट के लाभ:

- पर्यावरण संरक्षण:** स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
- आर्थिक प्रोत्साहन:** नवाचार और उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं को लाभ मिलता है।
- लचीलापन:** कंपनियों को लागत प्रभावी तरीके से उत्सर्जन सीमा का पालन करने का विकल्प।
- वैश्विक सहयोग:** जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:

- सत्यापन जटिलता:** क्रेडिट की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है।
- बाजार की अस्थिरता:** कीमतों में उतार-चढ़ाव स्थिरता को प्रभावित करता है।
- ग्रीनवाशिंग:** कंपनियाँ बिना ठोस बदलाव किए केवल छवि सुधार के लिए क्रेडिट का उपयोग कर सकती हैं।
- असमानता:** विकासशील देशों को संसाधनों तक पहुंचने में कठिनाई होती है।

भारत में कार्बन क्रेडिट का महत्व:

- नवीकरणीय ऊर्जा:** सौर, पवन और जलविद्युत परियोजनाएँ क्रेडिट उत्पन्न करती हैं।
- वनरोपण:** राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम उत्सर्जन में कमी लाता है।
- निर्यात अवसर:** भारतीय कंपनियाँ अधिशेष क्रेडिट बेचकर राजस्व अर्जित कर सकती हैं।
- सरकारी पहल:** प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना जैसी नीतियाँ ऊर्जा दक्षता और कार्बन क्रेडिट सृजन को बढ़ावा देती हैं।

इनडोर वायु प्रदूषण / Indoor air pollution

उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में **पीएम 2.5 के स्तर** पूरे साल विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सुरक्षित सीमा से अधिक बने रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

- ✓ WHO की रिपोर्ट बताती है कि प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख लोग जहरीली हवा के कारण समय से पहले अपनी जान गंवाते हैं।
- ✓ दुनिया के सबसे प्रदूषित 15 शहरों में से 12 शहर भारत के हैं, और वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के 30 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में भी भारत का वर्चस्व है। ऐसे में इनडोर वायु गुणवत्ता प्रबंधन एक आवश्यक कदम बन गया है।

इनडोर वायु प्रदूषण:

इनडोर वायु प्रदूषण का मतलब है घरों और इमारतों के अंदर की हवा में हानिकारक तत्वों या प्रदूषकों की मौजूदगी, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर उचित वेंटिलेशन (हवा का आवागमन) या एयर फिल्टरिंग सिस्टम न हो, तो ये प्रदूषक खतरनाक स्तर तक बढ़ सकते हैं।

इनडोर वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत:

1. **खाना पकाना:** ठोस ईंधन (लकड़ी, कोयला आदि) का उपयोग करने से हानिकारक गैसों और महीन कण निकलते हैं।
2. **खराब वेंटिलेशन:** आधुनिक चूल्हों के बावजूद, अगर रसोई में वेंटिलेशन सही नहीं है, तो प्रदूषक जमा हो सकते हैं।
3. **धूप और मोमबत्तियां जलाना:** धूप और मोमबत्तियों से महीन कण और वाष्पीय जैविक यौगिक (VOCs) हवा में मिलते हैं।
4. **लिंग आधारित प्रभाव:** महिलाएं, जो आमतौर पर रसोई में ज्यादा समय बिताती हैं, इन प्रदूषकों से अधिक प्रभावित होती हैं।

वायु प्रदूषण को मापने के तरीके:

1. **स्वतंत्र निगरानी की आवश्यकता:** कई इमारतों, कार्यस्थल और जिम अपने एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम की दायेदारी करते हैं, लेकिन बिना स्वतंत्र निगरानी के इन दावों की पुष्टि करना मुश्किल होता है।
2. **सस्ती एयर क्वालिटी सेंसर का उपयोग:** इनडोर PM2.5 स्तरों को मापने के लिए कम लागत वाले सेंसर का उपयोग करें। यह जांचने में मदद करता है कि अतिरिक्त फिल्ट्रेशन की आवश्यकता है या नहीं।
3. **एयर प्यूरीफायर में निवेश:** जिन घरों में सेंट्रलाइज्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है, खासकर उत्तर भारत जैसे क्षेत्रों में जहां बाहरी हवा लगातार प्रदूषित रहती है, वहां एयर प्यूरीफायर में निवेश करना आवश्यक हो जाता है।
4. **दृष्टि पर निर्भरता से बचें:** केवल साफ हवा देखकर या मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर वायु प्रदूषण का अंदाजा लगाना गलत हो सकता है।
5. **सटीक आंकड़ों पर ध्यान दें:** नजदीकी वायु गुणवत्ता मॉनिटर से प्राप्त डेटा को जांचें। इससे न केवल सही जानकारी मिलती है, बल्कि इनडोर वायु गुणवत्ता प्रबंधन की आवश्यकता पर भी जोर दिया जाता है।

वायु प्रदूषण को मापने और नियंत्रित करने के तरीके:

1. **एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम के दावे:** कई इमारतों, कार्यस्थल और जिम एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम का दावा करते हैं, लेकिन बिना स्वतंत्र निगरानी के इनकी पुष्टि करना मुश्किल होता है।
2. **PM2.5 स्तर मापना:** कम लागत वाले एयर क्वालिटी सेंसर का उपयोग करके इनडोर PM2.5 स्तरों को मापा जा सकता है। इससे यह पता चलता है कि क्या अतिरिक्त फिल्ट्रेशन की आवश्यकता है।
3. **एयर प्यूरीफायर का उपयोग:** जिन घरों में सेंट्रलाइज्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है, खासकर उत्तर भारत जैसे प्रदूषित क्षेत्रों में, वहां एयर प्यूरीफायर लगाना जरूरी हो जाता है।
4. **HEPA फिल्टर का महत्व:** एयर प्यूरीफायर में HEPA (High Efficiency Particulate Air) फिल्टर PM2.5 जैसे महीन कणों को रोकने के लिए जरूरी है। आधुनिक प्यूरीफायर में ऐसे सेंसर होते हैं जो हवा की गुणवत्ता के आधार पर स्वतः फैन की गति को नियंत्रित करते हैं।
5. **DIY विकल्प:** कम बजट वाले लोग HEPA फिल्टर और पंखे का उपयोग करके खुद का प्यूरीफायर बना सकते हैं।
6. **CADR मेट्रिक:** क्लीन एयर डिलीवरी रेट (CADR) यह दर्शाता है कि एक प्यूरीफायर कितनी जल्दी एक कमरे की हवा को साफ कर सकता है। बड़े कमरों के लिए उच्च CADR वाले प्यूरीफायर अधिक प्रभावी होते हैं।
7. **ओजोन उत्पन्न करने वाले प्यूरीफायर से बचें:** ओजोन उत्पन्न करने वाले प्यूरीफायर हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अतिरिक्त प्रदूषक उत्पन्न करते हैं।
8. **कार के अंदर स्वच्छ हवा:** कार में एयर कंडीशनर को रिसर्क्यूलेशन मोड में उपयोग करें और खिड़कियां बंद रखें। यह बाहरी प्रदूषण को कम करता है, लेकिन साथ ही कार के एसी सिस्टम भी प्रदूषण बढ़ाते हैं।

SECI और H2Global Stiftung के बीच हरित हाइड्रोजन पर समझौता / Agreement on Green Hydrogen between SECI and H2Global Stiftung.

भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत, **सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI)** ने **H2Global Stiftung** के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

- ✓ इसका **उद्देश्य** ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देना है और बाजार आधारित तंत्र पर ज्ञान का आदान-प्रदान करना। इसके साथ ही भारत और आयातक देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है, ताकि वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में योगदान किया जा सके।

समझौता के मुख्य बिंदु:

लक्ष्य:

- बाजार आधारित तंत्र पर ज्ञान का आदान-प्रदान बढ़ाना।
- भारत और आयातक देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
- ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में योगदान देना।

यह सहयोग भारत को संयुक्त निविदाओं (joint tenders) की संरचना का अवसर प्रदान करता है, जो भारत के ग्रीन हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्न (derivatives) का निर्यात केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है।

भारत ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता और 2070 तक नेट-जीरो का लक्ष्य घोषित किया है। ग्रीन हाइड्रोजन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

हाइड्रोजन तत्व:

- हाइड्रोजन रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक H और परमाणु संख्या 1 है।
- यह सबसे हल्का तत्व है और ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है, जो सामान्य पदार्थ का लगभग 75% बनाता है।
- हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, गैर विषैले और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है।

हाइड्रोजन का निष्कर्षण:

- हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ मिलकर पाया जाता है।
- ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए इसे प्राकृतिक यौगिकों जैसे पानी से निकाला जाता है (पानी में दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं)।
- ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (जैसे पवन, सौर, या जल-विद्युत) का उपयोग करके, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है।
- इलेक्ट्रोलिसिस में पानी (H₂O) को हाइड्रोजन (H₂) और ऑक्सीजन (O₂) में विभाजित करने के लिए विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। जब यह बिजली नवीकरणीय स्रोतों से आती है, तो हाइड्रोजन को "ग्रीन" माना जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया का पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव होता है।



भारत की ग्रीन हाइड्रोजन योजना: 2070 तक नेट-जीरो और रोजगार सृजन

1. भारत का ग्रीन हाइड्रोजन लक्ष्य:

- भारत का उद्देश्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।
- इसके लिए \$100 बिलियन का निवेश और 125 गीगावाट नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता होगी।
- यह लक्ष्य प्रधानमंत्री के पंचामृत योजना से मेल खाता है, जिसमें 2030 तक 500 गीगावाट गैर-कोयला ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है।

2. ग्रीन हाइड्रोजन की मांग:

- भारत में 2050 तक हाइड्रोजन की कुल मांग 29 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक पहुंचने का अनुमान है।
- ग्रीन हाइड्रोजन की मांग 2050 तक 27.2 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) से अधिक होने का अनुमान है।
- मुख्य उद्योग: स्टील, उर्वरक, रिफाइनरीज और सड़क परिवहन।

3. रोजगार सृजन:

- 2018 में ग्रीन सेक्टर में 11 मिलियन लोग कार्यरत थे, और 2050 तक इस क्षेत्र में 42 मिलियन से अधिक रोजगार सृजन का अनुमान है।
- यह ग्रीन ऊर्जा क्षेत्र के लिए नए उद्योगों और रोजगार अवसरों के विकास की संभावना को दर्शाता है।

वैश्विक ताजे जल भंडार में गिरावट / Declining global fresh water reserves

सूखा और सिंचाई के लिए बढ़ती पानी की जरूरतों के कारण खेतों और शहरों में भूजल पर अधिक निर्भरता बढ़ रही है, जिससे भूमिगत जल आपूर्ति में लगातार गिरावट आ रही है।

अब **नासा और जर्मन उपग्रहों** द्वारा किए गए अवलोकनों के आधार पर वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने यह पाया है कि **मई 2014 से धरती पर ताजा और मीठे पानी की मात्रा में अचानक गिरावट आई है** और तब से यह कमी लगातार बनी हुई है।

ताजे जल के भंडारों में गिरावट:

वैश्विक स्थिति:

- वर्ष 2015 से 2023 के बीच, झीलों, नदियों और भूजल सहित भूमि पर संग्रहीत ताजे जल में 1,200 घन किलोमीटर की कमी आई है।
- लगभग आधे देशों में ताजे जल की गुणवत्ता में गिरावट आई है। 400 से अधिक नदी बेसिनों में जल प्रवाह में कमी देखी जा रही है, जिनमें कांगो बेसिन जैसे महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र भी शामिल हैं।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 नदियों के लिए पिछले तीन दशकों में सबसे सूखा वर्ष होगा, जिससे ताजे जल का संकट और बढ़ेगा।

भारतीय स्थिति:

- भारत में विश्व की 18% आबादी रहती है, लेकिन देश में ताजे जल के केवल 4% संसाधन हैं और यह पृथ्वी की सतह का सिर्फ 2.4% हिस्सा घेरता है।
- देश की आधी नदियाँ प्रदूषित हैं, और 150 से अधिक प्रमुख जलाशय अपनी भंडारण क्षमता के केवल 38% पर काम कर रहे हैं, जिससे जल संकट और बढ़ गया है।
- नीति आयोग के 2018 के जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार, भारत की बड़ी आबादी जल तनाव से प्रभावित है। करीब 600 मिलियन भारतीय जल की कमी से जूझ रहे हैं।
- पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्यों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिसके कारण जल स्तर में गंभीर गिरावट आई है।
- मध्य और पश्चिमी भारत के राज्य जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात अक्सर सूखे का सामना करते हैं, जिससे जल भंडार और भी घटते जा रहे हैं।

ताजे जल के स्तर में गिरावट के प्रमुख कारण

1. अल नीनो घटनाएँ:

- वर्ष 2014-2016 की अल नीनो घटना ने वैश्विक वर्षा के पैटर्न को प्रभावित किया, जिससे सूखा और जल संकट और भी बढ़ा।
- प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय जेट धाराएँ बदल गईं, जिससे पूरे विश्व में जलवायु संकट गहरा गया।

2. जलवायु परिवर्तन:

- जलवायु परिवर्तन के कारण असमान वर्षा और अनियमित मानसून जैसी समस्याएँ बढ़ी हैं, जिसके कारण सूखा और अनावृष्टि जैसी घटनाएँ बढ़ गईं।
- वर्षा के बाद तीव्र अपवाह और लंबे समय तक सूखा रहने से जल अवशोषण क्षमता में कमी आ रही है।
- जलवायु परिवर्तन से वाष्पीकरण की दर बढ़ी है, जिससे सूखा और जल संकट की स्थिति और गहरी हो रही है।

3. भू-जल का अत्यधिक दोहन:

- विशेष रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई के लिए भू-जल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जो जल स्तर में गिरावट का कारण बन रहा है।
- भू-जल का दोहन अधिक होने के कारण प्राकृतिक पुनःपूर्ति से जल स्तर को संतुलित रखना मुश्किल हो रहा है।

4. पारिस्थितिकी तंत्र की क्षति:

- वनों की कटाई और आर्द्रभूमि जैसे पारिस्थितिकी तंत्रों के नष्ट होने से जल धारण की क्षमता घट गई है।
- मृदा का अपरदन और भूमि की जल अवशोषण क्षमता कम होने से जल भंडारण पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।

5. कृषि पद्धतियाँ और प्रदूषण:

- अकुशल सिंचाई विधियों और जल की अधिक मांग वाली फसलों के कारण जल की बर्बादी हो रही है।
- औद्योगिक अपशिष्ट और अनुपचारित अपशिष्ट जल जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे जल की गुणवत्ता और उपलब्धता प्रभावित हो रही है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय / International Criminal Court

हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके पूर्व रक्षा मंत्री और हमास अधिकारियों के खिलाफ युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के बारे में:

- **स्थापना:** ICC पहला अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय है, जो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोपियों की जांच और अभियोग करता है।
- **रोम संधि:** ICC की स्थापना रोम संधि से हुई, जो 1998 में अपनाई गई और 2002 में प्रभावी हुई।
- **अधिकार:** ICC को 4 मुख्य अपराधों पर अधिकार प्राप्त है (जैसे युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध आदि)।

सदस्यता:

- 124 देश रोम संधि के सदस्य हैं।
- भारत, इज़राइल, अमेरिका, रूस और चीन रोम संधि के सदस्य नहीं हैं।
- 2015 में पैलेस्टाइन 123वां सदस्य बना और 2019 में मलेशिया 124वां सदस्य बना।

प्रशासन:

- **राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल:** हर सदस्य देश से एक प्रतिनिधि होता है, जो अदालत के प्रबंधन और विधायिका का हिस्सा होता है।
- **आधिकारिक भाषाएँ:** अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश।

लागू करना:

- ICC के फैसले बाध्यकारी होते हैं।
- ICC के पास अपनी पुलिस फोर्स नहीं है और यह संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए देशों के सहयोग पर निर्भर करता है।

अतिरिक्त घटक:

- **पीड़ितों के लिए ट्रस्ट फंड (2004):** यह पीड़ितों को सहायता, समर्थन और मुआवजा प्रदान करता है।
- **निरोध केंद्र:** यह गिरफ्तारियों को सुरक्षित और मानवीय तरीके से हिरासत में रखता है।
- **पूरकता सिद्धांत:** ICC राष्ट्रीय आपराधिक प्रणालियों की पूरक है और केवल तब अभियोग चलाता है जब राज्य इसे करने में सक्षम या इच्छुक नहीं होते।

रोम संधि के तहत ICC का क्षेत्राधिकार

- **जातीय संहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध:**
 - यदि अपराध सदस्य राज्य के नागरिक द्वारा, सदस्य राज्य की सीमा में या ऐसे राज्य में किए गए हों जिन्होंने ICC के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया हो।
 - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा भेजे गए मामलों में ICC कार्यवाही कर सकता है।
- **आक्रमण अपराध:**
 - UNSC द्वारा भेजे गए मामलों में, चाहे सदस्य राज्य हो या गैर-सदस्य राज्य।
- 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति पर ICC का अधिकार क्षेत्र नहीं।

ICC की सीमाएं:

1. **अधिकार क्षेत्र की कमी:** ICC देशों के सहयोग पर निर्भर करता है, क्योंकि इसकी अपनी पुलिस फोर्स नहीं है।
2. **कुछ देशों का अनुपस्थित होना:** भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों ने ICC की सदस्यता नहीं ली है।
3. **सहयोग में कमी:** कई सदस्य राज्य गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण में सहयोग नहीं करते।
4. **निगरानी की कमी:** ICC के अभियोजक और न्यायाधीशों की शक्तियों पर प्रभावी निगरानी नहीं है।
5. **पूर्वकालीन अधिकार क्षेत्र की कमी:** ICC केवल 2002 के बाद के अपराधों पर कार्यवाही कर सकता है।
6. **संसाधनों की कमी:** ICC को पर्याप्त मानव संसाधन और वित्तीय सहायता की कमी है।
7. **पक्षपाती होने के आरोप:** ICC पर पश्चिमी साम्राज्यवाद और अफ्रीका के खिलाफ पक्षपाती होने का आरोप है।

रोबोटिक डॉग / Robotic Dog

भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने रोबोटिक डॉग्स के साथ विशेष अभ्यास किया, जो सेना के विभिन्न अभियानों में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

- ✓ यह अभ्यास 14 से 21 नवंबर तक आयोजित किया गया, जिसमें 50 से अधिक जवानों ने भाग लिया और उनके साथ 10 रोबोटिक डॉग्स शामिल थे।

रोबोटिक डॉग क्या है?

रोबोटिक डॉग एक उन्नत तकनीक से बनाया गया मशीन है, जो कुत्ते की तरह दिखता है और उसके जैसे चार पैर होते हैं। यह मुख्य रूप से एक रोबोटिक उपकरण है, जिसे विभिन्न कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है।

इसे रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है और कुछ मॉडलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से स्वतः संचालन करने की क्षमता भी होती है।

रोबोटिक डॉग्स की खासियतें:

1. थर्मल कैमरा और रडार से लेस:

- ये डॉग्स छुपे हुए दुश्मनों को पहचानने और उनका पता लगाने में सक्षम हैं।
- 360 डिग्री घूमने वाले हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे और सेंसर्स के माध्यम से रियल टाइम डाटा प्रदान करते हैं।

2. ऊबड़-खाबड़ और कठिन इलाके:

- बर्फ, रेगिस्तान, ऊंची सीढ़ियों और पहाड़ी रास्तों पर भी आसानी से काम कर सकते हैं।
- ये बाधाओं को पार करते हुए जवानों को किसी भी खतरे से बचाने में सहायक हैं।

3. संचालन और संचार:

- ये रोबोटिक डॉग्स थर्मल कैमरों और रडार से लेस हैं, जो छिपे हुए दुश्मनों का पता लगाने में अत्यधिक सक्षम हैं।
- संचालन के लिए यह वाई-फाई और 4जी/एलटीई नेटवर्क का उपयोग करता है।
 - ✓ **वाई-फाई:** छोटी दूरी के लिए उपयोगी।
 - ✓ **4जी/एलटीई:** लंबी दूरी (10 किमी तक) के लिए इस्तेमाल होता है।
- रोबोटिक डॉग्स को 1 मीटर से 10 किमी तक की दूरी पर ऑपरेट किया जा सकता है।

4. ऊर्जा क्षमता:

- केवल एक घंटे की चार्जिंग के बाद, ये डॉग्स **10 घंटे तक लगातार कार्य** कर सकते हैं।

5. मिशन सहायता:

- इनका उपयोग निगरानी, दुश्मनों पर नजर रखने और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।
- सेना इनके जरिए दुश्मनों के ठिकानों पर सटीक गोलीबारी कर सकती है।

6. दुश्मन को पहचानना और खत्म करना:

- रोबोटिक डॉग्स ने इस अभ्यास में दुश्मनों को खोजने और उन पर सटीक कार्रवाई करने की क्षमता का प्रदर्शन किया।

7. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग:

- इन डॉग्स को विशेष रूप से बर्फीले और दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स (आपूर्ति) सुधारने के लिए तैनात किया जा रहा है।

IISc बेंगलुरु और रोबोटिक खच्चरों का विकास

भारतीय सेना की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, IISc बेंगलुरु ऐसे रोबोटिक खच्चरों के निर्माण में मदद कर रहा है, जो कठिन से कठिन रास्तों पर चलने और भारी वजन उठाने में सक्षम हैं।

स्वदेशी निर्माण पर जोर:

- भारतीय सेना ने **जनवरी 2023 में 100 रोबोटिक खच्चरों** की जरूरत को लेकर एक **प्रस्ताव (Request for Proposal - RFP)** जारी किया।
- सेना चाहती है कि ये रोबोटिक खच्चर पूरी तरह से स्वदेशी कंपनियों द्वारा बनाए जाएं।

रोबोटिक खच्चरों की आवश्यकता क्यों?

1. सैन्य शक्ति को मजबूत करना:

- रोबोटिक खच्चर सेना की **तकनीकी क्षमताओं** को बढ़ाकर दुर्गम इलाकों में उनकी कार्यक्षमता में सुधार करते हैं।
- ये सैनिकों के साथ काम करते हुए रसद (लॉजिस्टिक्स) और सहायता को तेज और प्रभावी बनाते हैं।

2. सैनिकों की मृत्यु दर को कम करना:

- दुर्गम और खतरनाक इलाकों में तैनात सैनिकों पर पड़ने वाले जोखिम को कम करने के लिए रोबोटिक खच्चरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- ये खच्चर सैनिकों का भार हल्का करते हुए, कठिन अभियानों में उनकी सहायता करते हैं।

3. सीमा सुरक्षा में चीन की बढ़त:

- **चीन पहले ही रोबोटिक तकनीक** का इस्तेमाल अपनी सीमा सुरक्षा और सैन्य अभियानों में कर रहा है।
- भारतीय सेना को अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसे रोबोटिक खच्चरों की आवश्यकता है, ताकि सीमा पर सुरक्षा मजबूत हो सके।

4. अभियानों में भागीदारी:

- ये खच्चर दुश्मनों का पता लगाने, रसद आपूर्ति, और बर्फीले/ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों में **सुरक्षित परिवहन** में भूमिका निभा सकते हैं।
- साथ ही, ये कठिन और खतरनाक सैन्य अभियानों को अधिक कुशल और सुरक्षित बना सकते हैं।

मेंढक की एक नई प्रजाति: राओर्चेस्टेस असाकग्रेसिस / A new species of frog: Raorchestes asakagrensis

SAKON (सालिम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री) की टीम ने मेघालय में एक नई मेंढक प्रजाति खोजी है। इस प्रजाति को 'राओर्चेस्टेस असाकग्रेसिस' नाम दिया गया है, जो गारो हिल्स के एमन असाकग्रे सामुदायिक रिजर्व के नाम पर रखा गया है। यह नाम उन लोगों के सम्मान में रखा गया है जिन्होंने इस खोज में सहयोग किया।

राओर्चेस्टेस असाकग्रेसिस के बारे में:

- ✓ यह मेंढक की एक नई प्रजाति है।
- ✓ इसका नाम मेघालय के गारो हिल्स स्थित 'एमन असाकग्रे सामुदायिक रिजर्व' के नाम पर रखा गया है, जहाँ यह खोजा गया।
- ✓ यह नाम स्थानीय समुदाय के संरक्षण प्रयासों में उनके सहयोग के सम्मान में दिया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- यह मेंढक 174 मीटर की ऊँचाई पर 'एमन असाकग्रे' में पाया गया।
- यह छोटा वृक्षवासी (arboreal) मेंढक अपनी नुकीली थूथन और स्पष्ट टायपैनम (कान की झिल्ली) के लिए विशेष है।
- नर का स्नाउट-वेंट लंबाई लगभग 20.49 मिमी होती है, जबकि मादा का आकार थोड़ा बड़ा होकर 22.8 मिमी तक होता है।
- नर शाम के समय झाड़ियों पर बैठकर लगभग 1.5 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई से आवाज करते हैं। उनकी कॉलिंग गतिविधि मानसून की पहली बारिश के बाद अधिक होती है।



मेघालय: एक परिचय

स्थापना और भौगोलिक स्थिति:

- मेघालय का अर्थ है "बादलों का निवास"।
- 21 जनवरी 1972 को यह असम से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना।
- यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है और बांग्लादेश व असम से घिरा हुआ है।

राजधानी और प्रशासन:

- राजधानी और सबसे बड़ा शहर शिलांग है।
- यहां एकसदनीय विधानमंडल है और आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है।
- ✓ मुख्यमंत्री: कॉनराड संगमा
- ✓ राज्यपाल: सी. एच. विजयशंकर

भौगोलिक विशेषताएं:

- क्षेत्रफल: 22,429 वर्ग किमी।
- प्रमुख ऊँचाई: लुशाई हिल्स (1,965 मीटर)।
- यह भारत का सबसे अधिक आर्द्र क्षेत्र है, जहां खासी हिल्स में औसतन 12,000 मिमी वर्षा होती है।
- राज्य का लगभग 70% भाग वनों से आच्छादित है।

संस्कृति और परंपरा:

- मेघालय में मातृसत्तात्मक समाज है, जहां वंश और संपत्ति का अधिकार महिलाओं को दिया जाता है।
- इसे "पूर्व का स्कॉटलैंड" भी कहा जाता है।

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान / Ustad Bismillah Khan

संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत 22 नवंबर 2024 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में विशेष समारोह में 2022 और 2023 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 82 युवा कलाकारों को प्रदान करेंगे।

मुख्य बिन्दु:

- ✓ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार (UBKUP) संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2006 में शुरू किया गया एक प्रतिष्ठित सम्मान है।
- ✓ यह पुरस्कार भारत के युवा प्रदर्शनकारी कलाकारों को उनकी उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है।
- ✓ इसका उद्देश्य संगीत, नृत्य, नाटक, लोक एवं जनजातीय कला, कठपुतली कला और अन्य प्रदर्शन कलाओं में युवाओं को प्रोत्साहित करना है। यह पुरस्कार भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर रखा गया है।

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के बारे में:

- **स्थापना:** यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2006 में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर स्थापित किया गया था।
- **उम्र सीमा:** यह पुरस्कार 40 वर्ष तक के युवा कलाकारों को दिया जाता है।
- **क्षेत्र:** पुरस्कार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक एवं जनजातीय कला, कठपुतली कला और अन्य प्रदर्शन कलाओं में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है।
- **वर्षिक वितरण:** यह पुरस्कार हर साल दिल्ली और दिल्ली के बाहर विशेष समारोह में प्रदान किया जाता है।
- **इनामी राशि:** पुरस्कार में 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये), एक प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र (अंगवस्त्र) दिया जाता है।
- **उद्देश्य:** युवा कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और जनजातीय कला, और अन्य प्रदर्शन कला क्षेत्रों में प्रोत्साहित और प्रेरित करना।



उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में:

- **पूरा नाम:** उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जन्म नाम कमरुद्दीन खान
- **जन्म और मृत्यु:** 21 मार्च 1916 को जन्मे और 21 अगस्त 2006 को निधन हुए।
- **संगीत में योगदान:** उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका शहनाई बजाने का अंदाज इतना आकर्षक था कि वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रमुख कलाकार बन गए।
- **धार्मिक सद्भावना:** वे एक समर्पित मुसलमान थे, लेकिन हिन्दू और मुस्लिम दोनों प्रकार के समारोहों में प्रस्तुति देते थे। उन्हें धार्मिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता था।
- **स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:** 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराने के समय उन्होंने शहनाई बजाई।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि:** उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने 1966 के बाद विदेशों में भी प्रस्तुति दी, जब भारतीय सरकार ने उन्हें एडिनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद उनकी प्रसिद्धि पश्चिमी देशों में भी बढ़ी।
- **उपलब्धियाँ और पुरस्कार:**
 - **भारत रत्न (2001):** भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
 - **पद्मभूषण (1968)**
 - **पद्मश्री (1961)**
 - **संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (1956)**

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !



ANKIT AVASTHI



RRB NTPC

TEST SERIES

- ✓ 100+ Mock Test
- ✓ 78 Sectional Test
- ✓ 40+ years PYPs
- ✓ 60+ Current affairs

TEST



Only

99 *Per Year*

Buy Now



GA FOUNDATION

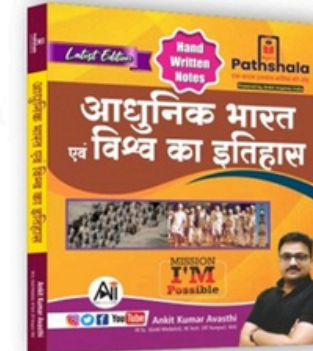
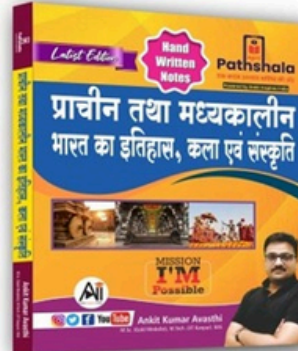
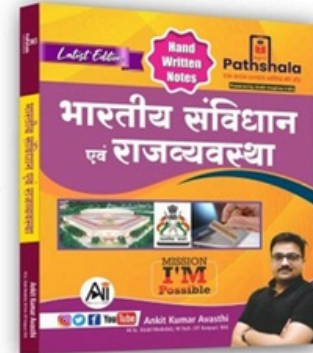
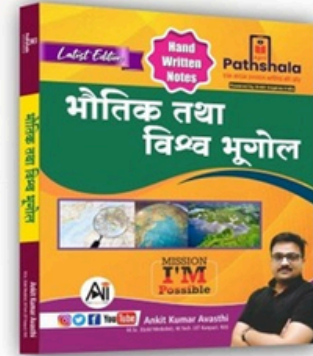
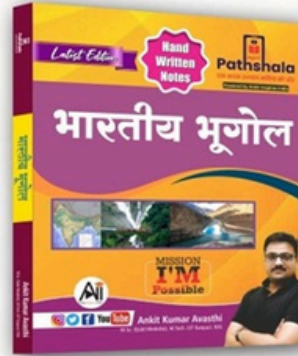
Hand Written
Notes


Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर


Ani
Ankit Inspires India

₹ **Only**
1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट



अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

 **7878158882**



APNI PATHSHALA

UPPSC, RO/ARO, BPSC, UP

TEST SERIES

UPPSC

(TEST SERIES)

- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

RO/ARO

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

BPSC

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299
YEAR

SSC

(TEST SERIES)

- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR

RPF

(TEST SERIES)

- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR



Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

▶ POLITY ▶ ECONOMICS
▶ HISTORY ▶ GEOGRAPHY

FOR ALL

LIVE DAILY LIVE CLASSES

WEEKLY TEST

CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)

LIVE DOUBT SESSIONS

DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs

4999/-



Apni Pathshala



7878158882



Apni.Pathshala



kaankit



AnkitAvasthiSir



Avasthiankit

ONLY POLITY



1499
RS

DAILY LIVE CLASSES

-  **WEEKLY TEST**
-  **CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)**
-  **LIVE DOUBT SESSIONS**
-  **DAILY PRACTISE PROBLEM**

Apni Pathshala



7878158882



Apni.Pathshala



kaankit



AnkitAvasthiSir



Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)



Only at

99/- Year

Enroll Now!

